International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 04, No. 01(II), January - March, 2022, pp.159-161

असंगठित क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

डॉ. जगदीश प्रसाद मीना*

i:Lrkouk

देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान असंगठित क्षेत्र का है। जिसमें कार्यरत लोगों का 85% हिस्सा है। भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से है जो अपने गांव में पुश्तैनी कार्य करते है। इनमें अधिकतर ऐसे लोग है जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांवों में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों और महानगरों में आजीविका तलाशते है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में कम है, बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती। इसके अलावा कृषि एवं निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार गारंटी न होने कारण इनमें मनोरोग का खतरा भी संगठित क्षेत्र के कामगारों से अधिक होता है।

आर्थिक मंदी और आपदा की स्थिति में बेरोजगारी की पहली और सबसे बड़ी मार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों पर पड़ी। कोराना महामारी की दूसरी लहर ने इस क्षेत्र पर एक फिर से ताले लगा दिए हैं। पीएमआईड़ी के अनुसार अलग–अलग राज्यों मे लागू सख्त पाबंदियों के कारण अकेले अप्रेल महीने में 75 लाख लोग बेरोजगार हो गए है। इसमें तीन चौथाई हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है। हाथी सवारी पर प्रभाव : राजस्थान के किलों पर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के हाथी की सवारी कराई जाती है। लेकिन पर्यटक नहीं आने से इनका और हाथी का भरण–पोषण करने का संकट पैदा हो गया है। विदेशी मुद्रा अर्जन में कमीः विश्व में पर्यटन को एक महत्त्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। भारत को भी पर्यटन से प्रति वर्ष अरबों रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें राजस्थान का काफी ऊँचा योगदान होता है लेकिन कोरोना महामारी ने इसे कम कर दिया है। कलात्मक धरोहरों के संरक्षण पर प्रभावः पर्यटन से आय नहीं होने से इन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों एवं इनकी देखभाल की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

असंगठित क्षेत्र का आर्थिक प्रभाव

कोरोना महामारी से यदि सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। वह है पर्यटन उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में या जी.डी.पी. में इस उद्योग का योगदान करीबन 6.8 फीसदी रहता है। भारत में पर्यटन उद्योग में करीब 8.75 करोड लोग जुड़े है। 2018–19 के आंकड़ो के अनुसार यह रोजगार का करीब 12.75 फीसदी है जिसमें करोड़ों लोगों के सामने आजीविका चलाने का संकट पैदा हो गया। इनको आजीविका चलाने के लिए दर–दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पर्यटन उद्योग से सीधे तौर पर कई और उद्योग भी जुड़े हुए है। ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल के 2019 के आंकडों के आधार पर स्टेटिस्टा ने सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची तैयार की है। सी.एन.एन. के अनुसार इस सूची में सबसे पहले मेक्सिको और उसके बाद स्पेन और इटली जैसे देश आते है। भारत की जे.डी.पी. इस पर्यटन उद्योग का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित

* सहायक आचार्य ई.ए.एफ.एम., स्व. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदीकुई, दौसा, राजस्थान।

पर्यटन और होटल व्यवसाय के लिए सरकार को एक विशेष कोष बनाना चाहिए और कर्ज अदायगी की छूट को और आगे बढ़ाना चाहिए। यात्रा एवं पर्यटन कोष स्थापित किया जाना चाहिए। आर.बी.आई द्वार कर्ज अदायगी को एक वर्ष की छूट देनी चाहिए। जी.एस.टी. में भी एक वर्ष की छूट दी जानी चाहिए।

कृषि क्षेत्र के उत्पादन का प्रभावः– कोविड़–19 का प्रभाव किसी एक विषय क्षेत्र पर ही नहीं पड़ा बल्कि यह भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसमें प्रभावित हुई है। अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्र और उनमें काम करने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित है, जिसमें कृषि क्षेत्र प्रमुख है। देश का किसान इस समय कोविड़–19 वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है, इसमें पहले किसान प्राकृतिक आपदा जैसे कम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, तेज तूफान आदि आपदाओं से जूझ रहा था। ऐसे में लॉकडाउन (तालाबन्दी) से देश के सब्जी, फल, दूध, मुर्गीपालन, पशुपालक, मधुमक्खीपालक, किसान आर्थिक चुनौतियो से जुझ रहा है, कोरोना महामारी से इनको उचित कीमत नहीं मिल रही है, जिसमें प्रभावित होकर किसान आगे कि खेती नहीं करना चाहता है। लॉकडाउन भारत में ऐसे समय शुरू हुआ जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार थी खरीफ की फसल का काम शुरू हो गया था। देश के तमाम हिस्सो से खबरे आई कि फूल, फल, सब्जीयाँ खेत में सड़ने लगी, ग्रामीण क्षेत्रों में इनके इंतजाम के लिए कोई भण्डारण व्यवस्था नहीं थी। बाजारों से जोड़ने वाली चैन खत्म हो गई। फल व सब्जियाँ खेत में सड़ गए। क्रेडिट लुईस के अनुसार किसानों को फल और सब्जियों के दाम गिरने व सड़ने के कारण लगभग 20 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। कोरोना महामारी के फैलने से फसलों की कीमतें कमजोर हो गई है, एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 6 वर्षों में धीमी गति से बढ़ रही है, मक्का, सोयाबीन, कपास और प्याज जैसी फसलों की कीमतें तक गिर गई है।

कोविड़ महामारी के बढ़ते प्रभाव के बीच शहरों की आबादी गाँव की तरफ वापस गई है, ऐसे समय में एक नई योजना के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान की परिकल्पना की जा सकती है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पादों के भण्डारण और क्रय–विक्रय केंद्रो की व्यवस्था की जाए। यदि हम किसी एक लाभदायक व्यवसाय के रूप बदलने में कामयाब रहे तो एक बड़ी आबादी गांव में ही रूक जाएगी। इससे शहरों में जनसंख्या के घनत्व के रूप में बढ़ रहे एक संकट में कमी आएगी।

असंगठित क्षेत्र का सामाजिक प्रभाव

वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र ही एक ऐसी कड़ी है जो भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः सुचारू ढंग से चला सकती है देश में पहले से ही आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों को निरन्तर सरकारों की ओर से उपेक्षित किया गया है। एन.एम.एस.ओ के अनुसार भारत के कुल कार्य क्षेत्र का 90 हिस्सा असंगठित व्यवसाय में लगा हुआ है इसका मतलब है कि लोग किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित है ये ऐसे लोग किसी भी संकट की स्थिति में पहले से ज्यादा प्रभावित हुए है। सरकारों को इस ओर ध्यान देने की जरुरत है। आईएफडी के अध्यक्ष गिलबर्ट एफ होंगबों ने 15 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय ग्रमीण महिला दिवस के मौके पर कहा कि हमारे खाने के लिए अनाज उगाने वाली और सबसे ज्यादा जोखिम में है। उन्होंने कहा कि वैश्विक लचीलापन इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारें ग्रमीण महिलाओं की रक्षा के लिए अपने सामाजिक–आर्थिक प्रभावों पर कितना अधिक ध्यान देती है। ग्रमीण महिलाएं जो कि बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के औपचारिक तौर पर हासिल करती इस महामारी के दौरान पुरुषों के मुकाबले सबसे ज्यादा ग्रमीण महिलाएं बेरोजगारी का सामना कर रही है, होंगबो ने कहा कि ग्रमीण महिलाएं जिन लोगों पर अगली पीढ़ी को खिलाने और पालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें इस संकट के माध्यम से उपेक्षित किया गया है।

कोविड–19 का प्रभाव फसल के लिए बीज, ट्रेक्टर, लेबर सहायता, दवाओं जैसे उत्पादों की अनुपलब्धता के कारण फसलों की बुवाई और कटाई में देरी है। सरकार को इन चीजों को उपलब्ध कराना चाहिए। सरकारों को ग्रमीण क्षेत्रों को समान प्राथमिकता देना बहुत महत्त्वपूर्ण है, यह क्षेत्र उपयोग की पटरी पर लाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार को गांव स्तर पर फसलों की खरीददारी की सुचारु व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों के उत्पादों पर यातायात खर्च बचाया जा सकें। वर्तमान परिदृश्य में कृषि क्षेत्र में काम कर

रहे ई–कॉमर्स खिलाड़ी गेमचेन्जर हो सकते है उनके पास किसानों का एक टारगेस बेस है जो सीधे सरकार द्वार प्राप्त किया जा सकता है जिससें समय के अन्तराल को कम किये जा सकता है। राज्य सरकारें तहसील स्तरों पर बारीकी से काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों की उपज को बाजार को बाजार तक भेजने के लिए कृषि इन्पुट मिल सकें।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर असंगठित क्षेत्र का प्रभाव

हमारे देश में लघु उद्योग एवं छोटे कारखानों की संख्या सबसे ज्यादा है। कोरोना महामारी के कारण इनको नगदी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बैंको से ऊँचे ब्याज पर कर्ज लेकर कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। कोरोना का सबसे गंभीर सामाजिक प्रभाव उन समुदायों पर देखने को मिलेगा जो आर्थिक तौर पर बेहद पिछड़े हुए है। जैसे घूमने वाले समुदाय के लोग, दिहाडी मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार इत्यादि। क्योंकि इनके रोजगार का डर बना हुआ है।

कोरोना का असर 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता रहेगा और दुनिया की बडी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवतस्था को इस महामारी के प्रकोप की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनोमिक्स ने ताजा ग्लोबल रिर्पोट में आकलन रखा है कि 2025 तक भारत की जी.डी.पी. कोविड़ से पहले के मुकाबले 12 प्रतिशत तक नीची रहेगी। आईएलओ के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में ढ़ाई करोड़ नौकरियां खतरे में है। देश की अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को सकारात्मक सोच के साथ कदम उठने चाहिए जिसमें देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सकें।

निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से भारत में 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के लोगों के सामने रोजी–रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन श्रमिको के घर बैठने पर उद्योग जगत पर गहरा असर पड़ा है। इसमे भारत के आर्थिक विकास की गति धीमी होना तय है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कोविड़–19 की महामारी के चलते भारत के अंसगठित क्षेत्र के काम करने वाले करीब 40 करोड़ लोग दलदल में फंस गये है। इस वित्तिय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की गिरावट के चलते संगठित क्षेत्र में सुस्ती के संकेत दिखाई दे रहे है। जो अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में और भी बुरे हालात है। यह कहा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिको में से अधिकांश को न तो सरकार की ओर से तय न्यूनतम वेतन मिलता है और न ही पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी कोई सामाजिक सुरक्षा इन्हें मिल पाती है। उन्हें चिकित्सा, देखभाल, दुर्घटना, मुआवजा, वेतन, सहित अवकाश और पेंशन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए समग्र नीति बनायी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत की अर्थव्यवस्थाः डॉ. ओ. पी. शर्मा
2. भारत का आर्थिक पर्यावरण : डॉ. बी. पी. गुप्ता
3. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिर्पोट–2020
4. केन्द्रीय बैंक : 2021 की मौद्रिक रिर्पोट
5. राजस्थान पत्रिका :आलेख, जनवरी 2021
6. अमर उजाला : आलेख, मई 2021
7. सम्पादकीय आलेखः दैनिक भास्कर
8. कोविड–19 पर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बेबीनार

❖◆❖